

प्रेषक,

सुशील कुमार,  
सचिव (प्रभारी),  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
अल्मोड़ा।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 02 दिसम्बर, 2020

विषय:- देघाट, जिला अल्मोड़ा में केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने हेतु 0.113 है० (05 नाली 10 मुट्ठी) भूमि केन्द्रीय विद्यालय संगठन के पक्ष में आवंटन करने सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1432/सत्ताईस-29/2007-08, दिनांक 19 दिसम्बर, 2019 तथा पत्र संख्या-5396/सत्ताईस-29/2007-2008, दिनांक 31 अगस्त, 2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा देघाट जिला अल्मोड़ा में केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने हेतु राज्य सरकार की 0.113 है० (05 नाली 10 मुट्ठी) भूमि जो श्रेणी-9(3)ड बंजर काबिल आबाद में दर्ज अभिलेख है, को केन्द्रीय विद्यालय संगठन के पक्ष में आवंटन करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिए गये निर्णय के प्ररिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि देघाट जिला अल्मोड़ा में केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने हेतु राज्य सरकार की 0.113 है० (05 नाली 10 मुट्ठी) भूमि जो श्रेणी-9(3)ड बंजर काबिल आबाद में दर्ज अभिलेख है तथा जिसका नजराना रू० 3,93,750/- (रूपये तीन लाख तिरानब्बे हजार सात सौ पचास मात्र) है तथा मालगुजारी 95 पैसे (पिच्चानब्बे पैसे) है, की धनराशि में छूट प्रदान करते हुए वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-260/वित्त अनुभाग-3/2002 दिनांक 15 फरवरी, 2002, शासनादेश संख्या-111/XXVII(7)50 (39)/2015/2014 दिनांक 09 जुलाई, 2015, शासनादेश संख्या-1887/XVIII(II)/2015-18(169)/2015 दिनांक 30 जुलाई, 2015 तथा शासनादेश संख्या-1115/XVII(II)/2016-18(184)/2015 दिनांक 15 जून, 2016 के प्राविधानों के अन्तर्गत श्री राज्यपाल महोदय केन्द्रीय विद्यालय संगठन के पक्ष में निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।
- (2) जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी हो।
- (3) हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाय तो उसके लिये मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
- (4) यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 03 वर्षों तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।
- (5) जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना भूमि हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।

- (6) जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।
  - (7) प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जाय।
  - (8) यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो अथवा संस्था का विघटन हो जाता है तो भूमि/भवन सील सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।
  - (9) प्रश्नगत भूमि आवंटन के पूर्व उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भू-व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा-132 एवं अन्य सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
  - (10) इस सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या-1132/2011 (एस0एल0पी0)/(सी)संख्या-3109/2011 श्री जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
  - (11) आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तों बिन्दु संख्या-01 से 10 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।
- 3- कृपया इस सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश की प्रति, शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुशील कुमार)  
सचिव (प्रभारी)।

संख्या-1025/XVIII(II)/2020 तददिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव/सचिव, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- आयुक्त, कुमायूं मण्डल, नैनीताल।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4- निदेशक, केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्या0), शहीदजीत सिंह मार्ग, 18 संस्थागत क्षेत्र, नई दिल्ली-110016.
- 5- उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून।
- 6- निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय, देहरादून।
- 7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डॉ0 मेहरबान सिंह बिष्ट)  
अपर सचिव।